पानी की दरों में भेदभाव पर रेजीडेंट कन्फेडरेशन ने जताई नाराजगी

- सदन के प्रस्ताव पर सरकार से जताएंगे रोष
- एक ही शहर में एक ही एजेंसी की दो तरह की दरें अनुचित : जटवानी
- पानी की बढ़ी हुई दरों का प्रस्ताव रद्द करने की मांग

फरीदाबाद, उपमुख्य संवाददाता : नगर निगम सदन ने हुडा सेक्टरों व नगर निगम क्षेत्र के पुराने शहरों में पानी की दरों में भेदभाव पर ऑल हुडा सेक्टर्स रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की कन्फेडरेशन ने नाराजगी ज़ताई। कन्फेडरेशन के अध्यक्ष टीडी जटवानी ने कहा कि सदन द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति लेकर फिलहाल उसका गहन अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि एक ही शहर में एक ही एजेंसी द्वारा दो तरह की दरें अनुचित हैं।

गौरतलब है कि नगर निगम सदन ने 4 नवंबर को हुडा सेक्टरों में पानी की दर 2 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर और पुराने शहरों व कालोनियों में 1 रुपये 25 पैसे तय किए हैं। रिहायशी क्षेत्रों में इस भेदभाव के अलावा पूरे शहर के वाणिज्यिक, उद्योग व संस्थागत भवनों के लिए पानी की सप्लाई दर समान दर से बेशुमार बढ़ाई गई है।

कन्फेडरेशन के प्रधान जटवानी का कहना है कि असल में नगर निगम ने जो तर्क दर बढ़ाने के लिए रखी हैं वे बेमायने हैं, क्योंकि निगम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पानी पर खर्च की पूरी रिकवरी सुनिश्चित नहीं हो सकती। कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि निगम का पानी अनधिकृत कालोनियों में निशुल्क पिया जाता है। निगम प्रशासन को इस पानी का भुगतान अपने आप करना चाहिए। इसलिए पानी की आपूर्ति पर होने वाले पूरे खर्च की वसूली के लिए सभी लोगों पर भार डालना अनुचित है।

जटवानी ने कहा कि इस मुद्दे पर कन्फेडरेशन शीघ्र सरकार को तथ्यात्मक पत्र लिखेगी, जिससे सदन के प्रस्ताव को सरकार मंजूरी न दे।

उधर, पानी की दर बढ़ाने पर विपक्षी दलों ने भी राजनीति शुरू कर दी है। भाजपा की एनजीओ प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शक्ति विनायक और एनआईटी हलके से इनेलो के प्रधान संतोष शर्मा ने पानी की दरें बढ़ाने पर रोष जताया।

विनायक का कहना है कि सेक्टरों में नगर निगम पुराने ट्यूबवेलों से पानी दे रहा है, जिससे पूरे सेक्टरों में मिट्टी युक्त और बिना क्लोरीन डाले जलापूर्ति हो रही है।

नगर निगम प्रशासन हुडा से जो रेनीवेल का पानी खरीद रहा है वह पानी जवाहर कालोनी व एनआईटी फीडर के माध्यम से पुराने शहर में जा रहा है। इस पानी का सेक्टरों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार पानी की बढ़ी हुई दरों का प्रस्ताव रद्द करे, अन्यथा आने वाले चुनाव में भाजपा इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी।

इनेलो के ब्लाक अध्यक्ष संतोष शर्मा का कहना है कि नगर निगम सदन को छोटे दुकानदार व उद्योगों के लिए भी पानी दर इतनी अधिक नहीं बढ़ानी चाहिए थी।

Water charges

The recent hike in water charges by the Municipal Corporation of Faridabad (MCF), in the sectors developed by the Haryana Urban Development Authority (HUDA), is a matter of serious concern. Surprisingly, the inhabitants of HUDA sectors have been levied with 300 to 400 per cent increase in water rates while in areas and colonies under MCF control there is only a marginal hike. The confederation of residents welfare associations (CRWA) feels that different rates for different areas in one town seems illogical and arbitrary. CRWA general secretary A. S. Gulati said there is acute shortage of water in HUDA sectors and residents do not get water without booster for which they have to pay inflated electric bills. In addition, drinking water supplied by the civic body is contaminated and therefore not fit for drinking without using a water purifier RO system. In view of this, there is no justification for the increase in water rates. Gulati said the RWAs in various HUDA sectors are united on this issue and are holding discussions with the confederation to take up the matter with the MCF Commissioner soon. The CRWA will even move court if necessary, he said.

CRWA